इंसान अपने भीतर के विचारों को बदलकार बाहरी दुनिया में भी परिवर्तन ला सकता है।
– अज्ञात

कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद

जरूरत इस बात की है कि अमेरिका की तरह देश की कुछ बड़ी कंपनियों को उनकी विशिष्टता का मामूली सा ध्यान रखते हुए कम से कम समय में वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण, सुरक्षा सामग्री और जांच किट बनाने का काम सौंप दिया जाए।

राहुल जोशी।

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4000 का आंकड़ा पार कर गई है। रोजाना इसमें जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है वह चिंताजनक है। सवाल है कि संकट से निपटने में हमारे अब तक के उपाय कुछ कारगर भी हुए हैं या कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद में ही हम सब कुछ करते जा रहे हैं। यह सही है कि देश भर में सारे इंतजाम यथासंभव तेजी से किए जा रहे हैं।

बड़ी संख्या में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जरा भी शक पर लोगों को आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। कई लोग ठीक होकर घर भी आ चुके हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हमारे पास इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी साधनों का घोर अभाव है। डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ दिन–रात देखे बगैर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा उपकरणों की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है। इसके चलते न सिर्फ बीमारी से निपटना मुश्किल हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों के सामने जान का खतरा मंडरा रहा है। जैसे, अभी बहुत बड़ी तादाद में एन 95 मास्क की जरूरत है, पर सामान्य मास्क तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं।

कई जगहों पर डॉक्टरों को अपने गाउन 2–3 दिन तक लगातार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। हास्यास्पद बात यह कि कुछ अस्पतालों में उन्हें रेनकोट और हेल्मेट थमाकर कोरोना मरीजों का इलाज करने को कह दिया गया है। जहां–तहां नर्सेज को ग्लव्स और सैनिटाइजर की किल्लत झेलनी पड़ रही है। मुंबई के एक अस्पताल में सुरक्षा उपकरण के नाम पर एचआईवी सुरक्षा उपकरण थमा दिए गए।

सरकार का कहना है कि उसने विदेश से भारी मात्रा में उपकरण मंगाने का ऑर्डर दे रखा है। लेकिन उसकी डिलीवरी कब होगी, यह स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें एक महीना लग सकता है। जरूरत इस बात की है कि अमेरिका की तरह देश की कुछ बड़ी कंपनियों को उनकी विशिष्टता का मामूली सा ध्यान रखते हुए कम से कम समय में वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण, सुरक्षा सामग्री और जांच किट बनाने का काम सौंप दिया जाए। इसके लिए उनके स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

युद्धकाल में ऐसा होता है और आज के हालात लगभग वैसे ही हैं। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि कोरोना के कारण अन्य मरीजों की उपेक्षा न हो। देश के कई अस्पताल बाकी मरीजों को बाहर से ही लौटा दे रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर बच्चों का टीकाकरण रुक गया है। यह नहीं होना चाहिए, वरना देश के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा।

लॉकडाउन का एक हफ्ता बीतने के साथ ही लोगों के सामने आटा–दाल का संकट भी शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार को सोशल डिस्टैंसिंग के साथ–साथ कुछ जरूरी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनानी होगी।

भूख झेलने की बजाय

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

ऐसे में मजबूर लोगों ने भूख झेलने की बजाय अपनों के बीच जाकर अभावों में जीवन गुजारने को ही बेहतर विकल्प मान लिया और लोगों का कारवां लकदक महानगरों से बीमारू राज्यों की तरफ निकल पड़ा। करीब पैंतीस साल पहले अर्थशास्त्री आशीष बोस ने उत्तर भारत के चार राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू जैसा अपमानजनक नाम दिया था। आशीष बोस का तर्क था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को नकारात्मक हद तक यही चार राज्य प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि सड़कों पर जो हुजूम निकला, वह इन बीमारू राज्यों का ही है। बीमारू का अपमानबोध हटाने के लिए इन राज्यों में तमाम कदम उठाए गए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बंटवारा भी हो गया। लेकिन हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी में इससे कुछ खास बदलाव नहीं आया।

संपादकीय

राजदूतों को संदेश

कोरोना संकट ने साबित किया है कि विश्व स्तर पर ऐसी कोई प्रभावी प्रणाली है ही नहीं। डब्लूएचओ इस संकट में कमजोर और दिशाहीन संगठन के रूप में सामने आया है। इस नाते भारत ने स्पष्ट कहा कि इसमें संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नया संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करने पर भी जोर दिया जिसे सभी देशों ने स्वीकार किया।

इन बैठकों के द्वारा भारत ने विश्व के प्रमुख देशों के नेतृत्व का जमीर जगाने और स्वास्थ्य से लेकर मानव कल्याण तक के संदर्भ में नई विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर विचार के लिए उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की। बात कहां तक जाएगी, इसका कितना असर होगा, कहना कठिन है लेकिन इसका कुछ असर निश्चित रूप से हुआ। ज्यादातर नेताओं ने माना कि हमें कोरोना महामारी से उबरने का हरसंभव प्रयास करने के साथ–साथ स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर से निपटने को भी प्राथमिकता देनी है। समूह द्वारा 5 खरब डॉलर का कोष बनाने का जो निर्णय लिया गया है, उसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने विश्व भर के अपने राजदूतों और उच्चायुक्तों से बात की तो उनसे भी यही कहा कि हमें भारतीयों की चिंता करने के साथ–साथ यह भी देखना है कि जिस देश में आप हैं, वहां के लिए क्या कर सकते हैं। महामारी में फंसे देशों से भारतीयों के अलावा दूसरे देशों के नागरिकों को भी भारत ने निकाला है। विश्व मानवता की दृष्टि से भारत की यह भूमिका इतिहास का अमिट अध्याय बन सकती है।

वायरस के प्रकोप के लिए किसी को दोष देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अभी मौजूदा संकट से निपटने के उपायों पर बात होनी चाहिए।

अहम सवाल भी उठाए

अवधेश कुमार।

किसी भी देश के मूल संस्कार और उसके चरित्र की परख संकट के समय ही होती है। वैश्विक महामारी के मौजूदा संकट के दौरान अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश अपने अंदर के हालात से जूझने तक ही सीमित हो गए हैं। भारत अकेला देश है जिसने इसे विश्व मानवता की साझा चुनौती बताते हुए न सिर्फ बाकियों की चिंता की, बल्कि सभी देशों को साथ लाने की ठोस पहल भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर सार्क देशों का सम्मेलन हुआ और फिर उनकी ही पहल पर जी–20 की बैठक भी संपन्न हुई।

जी–20 का वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब है। प्रधानमंत्री ने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर उन्हें इसका वर्चुअल सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार किया। इसके बाद स्वयं भी ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क किया। संदेश यही था कि मानवता के इस संकट को हमें साझा चुनौती मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यह भारत का ही प्रभाव था कि इसमें 19 देशों के साथ यूरोपीय संघ, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन संपन्न हो जाने के बाद यह जितना आसान लगता है, उतना था नहीं।

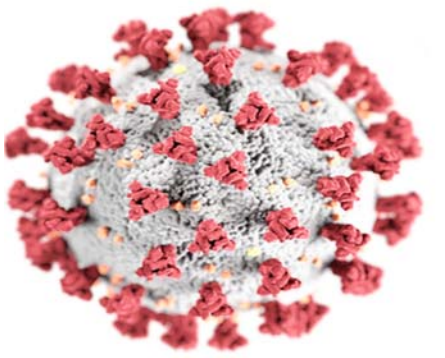

कोरोना वायरस के बारे में सही सूचना न देने के आरोप से घिरे चीन को लेकर कई देशों में नाराजगी है। कुछ देशों द्वारा चीन को निशाना बनाए जाने का खतरा था। मोदी ने अपने भाषण के आरंभ में यह कहकर माहौल बदल दिया कि यह वक्त इस पर चर्चा करने का नहीं है कि कोविड–19 का जन्म कहां हुआ। वायरस के प्रकोप के लिए किसी को दोष देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अभी मौजूदा संकट से निपटने के उपायों पर बात होनी चाहिए। इसका असर हुआ और सम्मेलन बिना किसी मतभेद के ठोस सहमतियों और फैसलों के साथ खत्म हुआ। भारत ने पहल नहीं की होती तो यह सम्मेलन आयोजित ही नहीं हो पाता। यही बात सार्क सम्मेलन पर भी लागू होती है।

सार्क या जी–20 का सम्मेलन यदि भारत नहीं बुलाता तो कहीं से आलोचना नहीं होती, पर हमारी राष्ट्र की अवधारणा में भारत के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का दायित्व है कि ऐसे समय वह विश्व की चिंता करें। सार्क सम्मेलन भी केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए एक कोष बनाने का प्रस्ताव रखा, अपनी ओर से एक करोड़ डॉलर का शुरुआती योगदान किया और यह वादा किया कि सभी सार्क देशों को अपनी विशेषज्ञता तथा संसाधन उपलब्ध कराएगा। जिन देशों को डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता होगी, उन्हें वह सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जी–20 की बैठक को भी अपने दृष्टिकोण से परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश भारत ने की और एक हद तक सफल रहा। प्रधानमंत्री ने इसमें कहा कि हम ज्यादातर आर्थिक मुद्दों पर बात करते रहे हैं जबकि हमारे सामने अनेक वैश्विक मुद्दे हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नए वैश्वीकरण की शुरुआत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने एक अधिक अनुकूल, उत्तरदायी और सस्ती जन स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने की बात की जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संकट से निपटने में मददगार हो।

सूडोकु नवताल-5308

सरल

		2				1		
				2	5	7	3	
	9	4		6	7			2
	5		4		3			9
	8			9			7	
1			6		8		2	
6			7	4		9	5	
	4	5	8	3				
		8				6		

Jagrutidaar.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5307 का हल

9	1	6	2	3	7	4	5	8
8	2	3	4	5	9	1	7	6
4	5	7	1	6	8	3	9	2
5	6	8	7	1	2	9	3	4
1	7	4	9	8	3	2	6	5
2	3	9	5	4	6	8	1	7
7	4	1	8	9	5	6	2	3
3	8	5	6	2	1	7	4	9
6	9	2	3	7	4	5	8	1

अपना ब्लॉग

मिल सकती है मोहलत

मोहन। नियम के अनुसार किसी सीट के खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर उसे भरना होता है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण पूरा देश ठप है। 26 मार्च को होने वाला राज्यसभा चुनाव तक स्थगित हो चुका है। जाहिर है, अभी चुनाव के बारे में किसी तरह का होम वर्क संभव नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार 22 सीटों पर उपचुनाव कराना एक बड़ी प्रक्रिया होगी और इसके लिए कम से कम तीन महीने की तैयारी करनी होगी। अभी इसकी तैयारी शुरू भी नहीं हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार लॉकडाउन जब समाप्त होगा, तब आगे की रणनीति पर विचार होगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की संवैधानिक बाध्यता के बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी कर तारीख बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार अब ये उपचुनाव बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ करवाए जा सकते हैं। बिहार में साल के अंत में अक्तूबर–नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।